भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1495

दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन

1495. श्री जी. सेल्वम:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और उक्त मिशन का भारत के आधुनिक तथा दक्ष ऊर्जा क्षेत्र के दृष्टिकोण के साथ एकीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त मिशन में शामिल विशिष्ट घटकों और प्रौद्योगिकियों, जैसे स्मार्ट मीटर, ऊर्जा भंडारण और मांग प्रतिक्रिया प्रणालियों की रूपरेखा प्रस्तुत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु सहित देश भर में एनएसजीएम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है और इन चुनौतियों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त मिशन के लिए अब तक कितनी निधि आवंटित/उपयोग की गई है;

(च) उक्त मिशन के तहत तमिलनाडु राज्य के लिए विशेष रूप से स्वीकृत और दिए गए स्मार्ट उपभोक्ता मीटरों की कुल संख्या कितनी है; और

(छ) उक्त मिशन के तहत अब तक उपरोक्त जिलों में लगाए गए स्मार्ट उपभोक्ता मीटरों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (छ) : भारत में स्मार्ट ग्रिड से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने और निगरानी करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में भारत सरकार (जीओआई) ने राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) की स्थापना की थी। एनएसजीएम को एनएसजीएम परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। यह स्कीम दिनांक 31.03.2024 को बंद हो गई है।

मिशन के प्रमुख घटक पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना मूल्यांकन, परियोजनाओं को वित्त पोषण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित परियोजना बनाने में सहायता थे। एनएसजीएम ने स्वदेशी स्मार्ट मीटर मानक आईएस16444 और सहायक मानक आईएस 15959 और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और डिजाइन बिल्ड

फाइनेंस ओन ऑपरेट ट्रांसफर (डीबीएफओओटी) मॉडल के लिए उन्नत मीटरिंग अवसंरचना सेवा प्रदाता (एएमआईएसपी) बोली दस्तावेजों के साथ स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम के विकास में योगदान दिया।

एनएसजीएम के अंतर्गत, उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्मार्ट मीटर परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं, जिसमें स्मार्ट मीटरिंग, हेड एंड सिस्टम, मीटर आंकडा प्रबंधन प्रणाली (एमडीएमएस) के साथ बहु संचार प्रौद्योगिकियां जैसे जनरल पैकेट रेडियो सेवा (जीपीआरएस)/रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) और पावर लाइन कैरियर (पीएलसी) आदि शामिल थीं।

एनएसजीएम के अंतर्गत, राजस्थान राज्य में 1,45,343 स्मार्ट मीटर और चंडीगढ़ में 24,214 स्मार्ट मीटर सफलतापूर्वक संस्थापित किए गए। तमिलनाडु राज्य के लिए एनएसजीएम के अंतर्गत कोई परियोजना संस्वीकृत नहीं की गई।

एएमआई, नई प्रौद्योगिकी होने के कारण, पर्याप्त कुशल जनशक्ति की उपलब्धता में चुनौतियां थीं। हालांकि, विद्युत मंत्रालय ने यूटिलिटी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर (एसजीकेसी), मानेसर जैसे संस्थानों के माध्यम से क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान की। एनएसजीएम के अंतर्गत लगभग 475 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया।

155.67 करोड़ रुपये के आवंटन में से, एनएसजीएम के अंतर्गत कुल 72.27 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

****